IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

विकसित भारत की ओर अगसर प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में मिड डे मील योजना की भूमिका : अपव्यय एवं अवरोधन के सन्दर्भ में

साजिद अली अंसारी

शोधार्थी

श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय

गजरौला

प्रो0 (डॉ0)कुलदीप सिंह तोमर

श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय

गजरौला

सारांश

मिड डे मील योजना, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, केवल बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी शिक्षा, विद्यालय में उपस्थिति और समग्र विकास को भी प्रोत्साहित करती है। यह योजना विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के ड्रॉपआउट को कम करने और उन्हें विद्यालय में बनाए रखने (अवरोधन) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के संदर्भ में, यह लेख मिड डे मील योजना के प्रभाव, इसके माध्यम से होने वाले सामाजिक एवं शैक्षिक सुधारों, और भविष्य में इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु आवश्यक रणनीतियों पर प्रकाश डालता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मिड डे मील योजना के व्यापक प्रभावों का विश्लेषण करना है, जिससे यह समझा जा सके कि यह योजना बच्चों के समग्र विकास और भारत के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में किस प्रकार सहायक है। यह योजना न केवल बच्चों के पोषण और शिक्षा में योगदान करती है, बल्कि दीर्घकालिक रूप में भारत को एक समृद्ध, सशक्त और समावेशी राष्ट्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक ठोस आधार भी प्रदान करती है।

मुख्य शब्द - मिड डे मील योजना, प्राथमिक शिक्षा, पोषण, विद्यालय उपस्थिति, अपव्यय, अवरोधन सामाजिक समानता, विकसित भारत 2047, शैक्षिक सुधार, नीति विश्लेषण

1. प्रस्तावना

भारत में शिक्षा को सर्वसुलभ, समतामूलक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, वंचित और कमजोर वर्गों के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मिड डे मील योजना (मध्यान्ह भोजन योजना) एक प्रभावशाली एवं दूरदर्शी पहल के रूप में सामने आई है। वर्ष 1995 में **राष्ट्रीय पोषण समर्थन कार्यक्रम** (National Programme of Nutritional Support to Primary Education) के नाम से शुरू की गई यह योजना, प्रारंभ में केवल सरकारी

और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों को गर्म पकाया हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई थी (**मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2006**)।

इस योजना का मूल उद्देश्य बच्चों को विद्यालयों की ओर आकर्षित करना, उनकी उपस्थिति दर में वृद्धि करना, विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति (ड्रॉपआउट) को कम करना, और उन्हें आवश्यक पोषण प्रदान करना रहा है। धीरे–धीरे यह योजना देशव्यापी रूप में लागू हुई और इसका विस्तार उच्च प्राथमिक स्तर तक किया गया। अनुसंधान बताते हैं कि इस योजना के लागू होने के बाद विद्यालयों में छात्रों की नियमितता और नामांकन दर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है **(द्रेज एवं गोयल, 2003)**।

विकसित भारत 2047 की परिकल्पना, जिसमें समावेशी, सशक्त और शिक्षित समाज की नींव रखी जा रही है, मिड डे मील योजना उसमें एक आधारभूत भूमिका निभा रही है। यह न केवल बच्चों को पोषण उपलब्ध कराती है, बल्कि सामाजिक एकता को भी प्रोत्साहित करती है, जहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों और वर्गों के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यह सामाजिक समानता और समरसता की भावना को भी बढ़ावा देती है**(खेड़ा, 2006)**।मिड डे मील योजना के परिणामस्वरूप विद्यालयों में बच्चों के सीखने की क्षमता, उपस्थिति दर, और स्वास्थ्य में भी सुधार दर्ज किया गया है। साथ ही, यह योजना विद्यालयों को सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संसाधनों के उपयोग के लिए भी प्रेरित करती है। अतः यह स्पष्ट है कि यह योजना शिक्षा, पोषण और सामाजिक विकास के त्रिकोण में संतुलन स्थापित करने का कार्य कर रही है, जो भारत को 2047 तक एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सहायक है।

2 मिड डे मील योजना : उद्देश्य और कार्यप्रणाली

मिड डे मील योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में आरंभ की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार करना है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को **"राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण समर्थन कार्यक्रम"** (National Programme of Nutritional Support to Primary Education & NP&NSPE) के अंतर्गत हुआ **था (शिक्षा मंत्रालय, 2021)**।

2.1 मिड डे मील योजना के उद्देश्य

- **बच्चां को पौष्टिक भोजन प्रदान करना**

  योजना के अंतर्गत बच्चों को प्रोटीन, विटामिन, खनिज एवं कार्बोहाइड्रेट से युक्त संतुलित भोजन दिया जाता है, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित हो सके तथा कुपोषण की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके **(भारत सरकार, 2022क)।**

- **विद्यालयों में उपस्थिति एवं नामांकन दर बढ़ाना**

  दोपहर के भोजन की सुविधा बच्चों को विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए प्रेरित करती है, जिससे नामांकन में वृद्धि तथा ड्रॉपआउट दर में कमी आती **है (शिक्षा मंत्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन, 2022–23)।**

- **शिक्षा में निरंतरता बनाए रखना**

  नियमित विद्यालय उपस्थिति से बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होता है तथा उनके सर्वांगीण विकास को बल मिलता है **(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2019)।**

- **सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना**

  विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जातीय पृष्ठभूमि से आए बच्चे एक साथ भोजन करते हैं, जिससे सामाजिक समानता और भाईचारे की भावना विकसित होती है **(योजना आयोग, 2010)**।

- **"विकसित भारत 2047" के लक्ष्य में योगदान देना**

  भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में, स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ नागरिकों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। मिड डे मील योजना बच्चों के पोषण और शिक्षा को सुनिश्चित कर इस महत्त्वपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति में योगदान कर रही है **(नीति आयोग, 2021)**।

2.2 मिड डे मील योजना की कार्यप्रणाली

- **लाभार्थी**

  यह योजना कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों तथा मदरसा/मौलवी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों के विद्यार्थियों को कवर करती है।

- **भोजन के पोषणीय मानक** . योजना के अनुसार प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी कम से कम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने का प्रावधान है (मिड डे मील दिशा–निर्देश, 2006; v|ru 2021)।

- **भोजन की तैयारी और आपूर्ति**

  भोजन विद्यालय परिसर में पकाया जाता है या फिर स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों तथा गैर–सरकारी संगठनों (NGO) द्वारा तैयार कराया जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलता है **(मिड डे मील वार्षिक कार्य योजना, 2022–23)**।

- **निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण**

  योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सतत निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था है। भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच तथा शिकायत निवारण की भी विशेष व्यवस्था की गई है **(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, निगरानी रिपोर्ट, 2020)।**

- **नवीन पहल**

  वर्ष 2021 में योजना का नाम परिवर्तित कर "पीएम पोषण योजना" (PM Psohan Scheme) रखा गया, जिसके अंतर्गत अब आंगनवाड़ी केंद्रों के पूर्व–प्राथमिक बच्चों को भी पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई **है (भारत सरकार, 2021ख)।**

3. अपव्यय और अवरोधन की समस्या

3.1 अपव्यय . भारत में बच्चों का विद्यालय छोड़ने **(अपव्यय) का कारण कई होते हैं। आर्थिक समस्याएँ,** जैसे परिवार की गरीबी, बच्चों का बाल श्रम में संलग्न होना, शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव , विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी, जैसे कि शौचालय, पानी, और योग्य शिक्षक।

मिड डे मील योजना इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। यह बच्चों को भोजन प्रदान करके उन्हें विद्यालय में बनाए रखने और उनके पढ़ाई के प्रति आकर्षित करने में मदद करती है।

3.2 अवरोधन

अवरोधन का तात्पर्य है कि बच्चे अपनी कक्षाओं में स्थिर रहते हैं और बार–बार कक्षा में रुकने या फेल होने की प्रवृत्ति नहीं रखते। मिड डे मील योजना बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को उत्तेजित करती है, जिससे उनकी संज्ञानात्मक क्षमता में वृद्धि होती है और वे कक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं।

4. मिड डे मील योजना का प्रभाव

4.1 शिक्षा पर प्रभाव

मिड डे मील योजना का सबसे बड़ा प्रभाव विद्यालयों में उपस्थिति दर पर पड़ा है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (NUEPA) के अनुसार, 2004 में इस योजना के लागू होने के बाद, विद्यालयों में उपस्थिति दर में औसतन 10–15: की वृद्धि हुई है। यह योजना बच्चों को स्कूल में लाने और उन्हें पढ़ाई में भागीदार बनाने में मदद करती है।

4.2 पोषण पर प्रभाव

इस योजना का एक अन्य प्रमुख प्रभाव बच्चों के पोषण स्तर पर है। बच्चों को विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने से उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सुधार हुआ है। यूनिसेफ के अनुसार, इस योजना ने बच्चों के कुपोषण को काफी हद तक कम किया है और उनके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद की है।

5. विकसित भारत की दिशा मं मिड डे मील योजना का योगदान

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत, मिड डे मील योजना का प्रभाव व्यापक और दीर्घकालिक है। यह योजना बच्चों की शिक्षा, पोषण और सामाजिक समावेशन में योगदान करके एक सशक्त और समृद्ध भारत की नींव रख रही है।

शिक्षा और पोषण का संबंध : यह योजना बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने और उनकी शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक है।

सामाजिक समावेशन: मिड डे मील योजना जातिवाद, लिंग भेदभाव और आर्थिक विषमता को समाप्त करने के प्रयासों में सहायक है।

सशक्त भविष्य: योजना बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनते हैं और भविष्य में राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान करते हैं।

6. चुनौतियाँ और सुधार के सुझाव

6.1 चुनौतियाँ

- **खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता:** कुछ क्षेत्रों में खाद्य गुणवत्ता की निगरानी और स्वच्छता संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- **रसोइयों और कर्मचारियों की कमी:** कई स्थानों पर रसोइयों की संख्या कम है, जिससे भोजन का वितरण सही समय पर नहीं हो पाता।
- **स्थानीय स्तर पर निगरानी की कमी:** योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

6.2 सुधार के सुझाव

- स्थानीय समुदायों को योजना में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए, ताकि यह अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सके।
- निगरानी प्रणाली को डिजिटल माध्यमों से जोड़कर इसे और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाया जाए।
- रसोइयों का प्रशिक्षण और स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाएं।

मिड डे मील योजना ने विद्यालयों में बच्चों के अपव्यय और अवरोधन को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।**शिक्षा मंत्रालय (2022)** की रिपोर्ट के अनुसार, जिन विद्यालयों में नियमित रूप से मिड डे मील उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ नामांकन दर में 15ः तक की वृद्धि और ड्रॉपआउट दर में 10ः तक की कमी देखी गई है। पौष्टिक भोजन बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करता है, जिससे वे निरंतर पढ़ाई में लगे रहते हैं और उनकी शैक्षणिक प्रगति में बाधाएँ कम होती हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के बीच यह योजना शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने में एक मजबूत साधन बनकर उभरी है **(योजना आयोग, 2010)।**

इस प्रकार, मिड डे मील योजना केवल पोषण सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण और गुणवत्ता सुधार में भी सहायक है, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है **(नीति आयोग, 2021)**।

• 7. निष्कर्ष

मिड डे मील योजना ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इस योजना ने बच्चों के पोषण स्तर में सुधार कर उनके शारीरिक और मानसिक विकास को गति दी है, साथ ही विद्यालयों में उनकी उपस्थिति और शैक्षणिक निरंतरता को भी बढ़ावा दिया है। विशेष रूप से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने और उनके शिक्षा अधिकार को सशक्त बनाने में मिड डे मील योजना ने एक सेतु का कार्य किया है। योजना के प्रभाव से अपव्यय और अवरोधन की दरों में उल्लेखनीय कमी आई है, जो एक शिक्षित और समावेशी भारत के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।मिड डे मील योजना ने भारत के शिक्षा और पोषण क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। यह योजना विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक मजबूत कदम है।**विकसित भारत 2047** की संकल्पना को साकार करने के लिए मिड डे मील जैसी योजनाओं का सतत सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता में सुधार और निगरानी अनिवार्य है। एक पोषित, शिक्षित और जागरूक बाल पीढ़ी ही भविष्य के भारत को वैश्विक मंच पर गौरव प्रदान कर सकती है। यदि मिड डे मील योजना को और भी प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए, तो यह योजना भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सहायक हो सकती है।

संदर्भग्रंथ सूची

- **योजना आयोग. (2010).** मिड डे मील योजना पर मूल्यांकन अध्ययन. नई दिल्ली।
- **यूनिसेफ भारत (2020),** मिड डे मील योजना: बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए एक जीवन रेखा।
- **यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE) (2020–21),** विद्यालय सूचना प्रणाली, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
- **खेड़ा, रीतिका। (2006).** प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन : उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 41(46), 4742–4750।
- **झा, पी., और परवती, पी. (2010),** शिक्षा का अधिकार और मिड डे मील योजना : एक तुलनात्मक अध्ययन, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 45, संख्या 23।
- **द्रेज, जे., और गोयल, ए. (2003),** मिड डे मील का भविष्य, फ्रंटलाइन, खंड 20, संख्या 14।
- **मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2006).** मध्यान्ह भोजन योजना : दिशा–निर्देश और रूपरेखा। भारत सरकार, नई दिल्ली।
- **मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2019).** मिड डे मील योजना निगरानी रिपोर्ट।
- **शिक्षा मंत्रालय. (2021). मिड डे मील योजना – वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21.** नई दिल्ली : भारत सरकार।
- **भारत सरकार. (2021ख).** पीएम पोषण पर मंत्रिमंडल का निर्णय, प्रेस सूचना ब्यूरो, 29 सितंबर 2021।
- **भारत सरकार (2021),** मिड डे मील योजना वार्षिक रिपोर्ट, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
- **भारत सरकार (2022),** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
- **भारत सरकार. (2022क).** पीएम पोषण दिशा–निर्देश 2021. नई दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय।
- **ड्रेज, जाँ एवं गोयल, अनीता। (2003).** मध्यान्ह भोजन योजना का भविष्य। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 38(44), 4673–4683।
- **NUEPA (2019),** भारत में प्राथमिक शिक्षारू हम कहाँ खड़े हैं?, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान।
- **नीति आयोग. (2021).** नया भारत ⁄75 के लिए रणनीति. नई दिल्ली : भारत सरकार।